(ख) सीधी ट्रंक डायलिंग सर्किट वहां जगायी जाती है जहा 3 या इससे अधिक ट्रक चैनल काम करते हों। बुरहानपुर और इन्दौर के बीच कैरियर प्रणाली की व्यवस्था कर के चेनलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। जब यह प्रणाली चालू हो जाएगी तो सीधे डायलिंग सर्किट की व्यवस्था कर दी जायेगी।

आकाशवाणी के मध्य प्रदेश स्थित केन्द्रों से मध्य प्रदेश के संसद्-सदस्यों और विधायकों की वार्ता

5230. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन संसद सदस्यों और मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के नाम क्या है जिनकी वार्ताएं वर्ष 1970–71 में और 1971–72 के अक्तूबर महीने तक मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाण केन्द्रों से प्रसारित की गई, और

(ख) यदि कोई वार्ता प्रसारित नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धमवीर सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

AIR Artistes on Hunger Strike

5231. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether some of the AIR Artistes went on a hunger strike in the month of November, 1972 as a protest against non-implementation of certain assurances;

(b) if so, the steps taken by Government;

(c) what are the demands which are still outstanding; and

(d) when final orders are likely to be issued in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) Certain staff artistes of AIR went on a relay fast in support of their demands.

(b) to (d) A statement is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-4103/72].

Prosecutions of Central Government Employees in connection with their participation in 1968 strike

5232. SHRI S M BANERJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state·

(a) whether Central Government employees at Delhi and elsewhere are still prosecuted for activities connected with September, 1968 strike of the Central Government employees and the Government have not yet issued necessary instructions to terminate/withdraw these cases in order to normalise the industrial relations;

(b) if so, the number of cases still pending in Delhi and elsewhere; and

(c) the steps Central Government propose to take to terminate these proceedings against the employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) to (c). According to the information received from the State Governments except Bihar, and the Union

Territories Administrations, upto November, 1972, 27 prosecution cases, including one case in Delhi, were pending against Central Government employees for their activities in connection with the Central Government employees' strike of September, 1968. Government's policy in regard to the prosecution of such employees has always been to allow the law to take its course, and not to interfere with the normal course of justice. However, the State Governments and the Union Territories Administrations concerned have been requested from time to time to take necessary steps for expediting the proceedings and also to have a careful scrutiny of the pending prosecution cases made with a view to terminating the proceedings according to law in cases in which the evidence is not considered sufficient.

Departmental leave in P. & T. Department

5233. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether employees in the Posts and Telegraphs Department are sent on Departmental Leave under Supplementary Rule 276; and

(b) if so, the total number of employees sent on Departmental Leave during the years 1970 and 1971?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) In the P. & T. Department, only seasonal staff, i.e., those employed for a part of a year, are eligible for the grant of Departmental Leave.

(b) Nil.

भारतीय मानक संस्था में पदों का आरक्षण

5234. **श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था पदों को आरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 1/3/63-एस० सी० टी० (1) दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के अनुसार, आरक्षण देने हेतु 40 प्वाइंट वाले माडल रोस्टर का पालन कर रही है; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय मानक संस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिए पदों के आरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/11/69, व्यवस्था (एस० सी० टी०), दिनांक 22 अप्रैल, 1970 के अनुसार, जिसके द्वारा उक्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/3/63- एस० सी० टी (1), दिनांक 21 दिसम्बर, 1963 में निर्धारित रोस्टरों की संशोधित किया गया है, आरक्षण देने हेतु 40 प्वाइंट वाले मांडल रोस्टरों का पालन कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय मानक संस्था में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या

5235. **श्री शिवशंकर प्रसाद यादव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयमानक संस्था में निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; (1) निदेशक, (2) उपनिदेशक, (3) सहायक निदेशक, (4) सहायक सचिव, (5) अनुभाग अधिकारी, (6) सहायक ;